भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1008

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की टुकड़ियां

†1008. श्री हरिवंश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सल प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कितनी टुकड़ियां तैयार की गयी हैं;
(ख) इन पुलिस बलों पर केन्द्र सरकार की कितनी राशि खर्च हो रही है और इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं; और
(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) : वर्तमान में, राज्य में वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियान चलाने के लिए राज्य पुलिस की सहायतार्थ 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के कुल 593 कंपनियां तैनात की गई हैं।

(ख) : दिनांक 01.04.2014 से, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक आगामी पांच वर्षों के लिए 5% वार्षिक वृद्धि के साथ बटालियन के परिवहन/संचालन की वास्तविक लागत के अतिरिक्त , प्रत्येक बटालियन (7 कंपनियों की) के लिए तैनाती प्रभारों की वसूली दर 43.10 करोड़ रु. प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। दिनांक 01.10.2014 की स्थिति के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सीआरपीएफ (सीएपीएफ में सबसे ब ड़ा बल) की तैनाती के संबंध में तैनाती प्रभारों के कारण 13139.37 करोड़ रु. की राशि बकाया है।

(ग) : वर्तमान में, सरकार के पास वामपंथी प्रभावित राज्यों में सीएपीएफ बटालियनों की संख्या कम करने तथा इस प्रकार, उनकी तैनाती संबंधी व्यय को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****